(b) and (c). One or two rural electricity co-operatives of each State Electricity Board area will be formed as a pilot project. If the experiment is found to be successful, the scheme would be extended further. The rural electricity co-operatives, when formed, will be closely linked with the rural industrial processing co-operatives. The programme of rural electricity co-operatives would be complementary to the activities of the State Electricity Boards in the field of rural electrification.

विदेशी मुद्रा

*761. श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रोटरी क्लब तथा लायन्स क्लब तथा अन्य ऐसे कितने क्लब हैं या संस्थायें हैं जिनका हैड आफिस (मुख्यालय) विदेशों में है ;

(ख) इन क्लबों द्वारा विदेशों में प्रति वर्ष कितना धन भेजा जाता है ; और

(ग) क्या इस तरफ सरकार का ध्यान है कि इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का अपव्यय होता है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). वर्तमान विनियमों के अनुसार, विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने वाले अधिकृत बैंकों को, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में किसी प्रार्थी को, वास्तविक क्लबों तथा वैज्ञानिक, तकनीकी और शिक्षा संस्थाओं को चंदे या सदस्यता शुल्क के रूप में 20 रुपये तक की विदेशी मुद्रा-भेजने की अनुमति देने का अधिकार है। सरकार के पास रोटरी क्लब और लायन्स क्लब के अपने-अपने मुख्यालय में भेजने के लिए विदेशी मुद्रा देने के लिए केवल दो प्रार्थना-पत्र भेजे गए थे। रोटरी क्लब को विदेशी मुद्रा की, एक-एक लाख रु० की दो रकमें भेजने की अनुमति क्रमशः दिसम्बर 1954 और जून 1956 में दी गयी थी। लायन्स इण्टरनेशनल को 1962 में 4,000 डालर भेजने की अनुमति दी गयी।

(ग) विदेशी मुद्रा में भेजी गयी कुल रकम और उसके फलस्वरूप होने वाला विदेशी मुद्रा का व्यय बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता।

Recruitment of Income-Tax Officers

*762. **Shri Rameshekhar Prasad Singh:**
Shri Himatsingka:
Shri P. H. Bheel:

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 891 on the 18th November, 1965 and state:

(a) whether all the Income-tax Inspectors who have passed the departmental examination and are otherwise duly qualified and are awaiting promotion as Income-tax Officers (Class II) have been absorbed in the existing vacancies of Income-Tax Officers (Class II); and

(b) if not, the reasons for not considering their cases and going in for *ad hoc* recruitment on such a large scale?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) No, Sir.

(b) The reasons for *ad hoc* recruitment generally are to infuse new blood, select people from a larger sphere and to further improve the tone and standard of the service.